क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480 सह संपादक : संदीप मौर्या
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 261, मंगलवार, 16 अक्टूबर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

रोहिंग्या शरणार्थियों का आधार कार्ड होगा रद्द

नई दिल्ली (संवाददाता)। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) कार्ड धारक रोहिंग्या शरणार्थियों में से उन सभी के आधार

कार्ड रद्द किए जाने जिन्होंने इस यूएनएचसीआर कार्ड के आधार पर हासिल किया था। केन्द्र सरकार ने इसके लिये सभी राज्य सरकारों से आधार कार्ड धारक रोहिंग्या शरणार्थियों के आंकड़े जुटाने को कहा है। भारत में यूएनएचसीआर कार्ड धारक लगभग 4.5 लाख रोहिंग्या शरणार्थी दिल्ली सहित कई राज्यों में रह रहे हैं। केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने अवैध शरणार्थियों को जारी हुए आधार कार्ड रद्द करने के बारे में सभी राज्य सरकारों से कहा है कि आधार कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को जारी किया जा सकता है जो भारत में वैध रूप से रह रहे हैं। मंत्रालय में विदेशी नागरिकों से संबंधित इकाई द्वारा राज्यों के गृह विभाग और पुलिस महानिरीक्षक को अवैध प्रवासियों की पहचान कर इनके आंकड़े मुहैया कराने को कहा है। मंत्रालय की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश पहले ही दिया जा चुका है कि देश में अवैध प्रवासियों और अवैध निवासियों को किसी भी प्रकार से आधार कार्ड जारी न किया जाए। गृह मंत्रालय ने कहा कि शरणार्थियों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के 1951 और 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत शामिल नहीं है। इसलिए यूएनएचसीआर कार्ड के आधार पर भारत में विशिष्ट पहचान संबंधी आधार कार्ड जारी करने का औचित्य नहीं है। मंत्रालय ने इस बात से इंकार नहीं किया कि यूएनएचसीआर कार्ड अवैध आप्रवासियों को भी जारी हो चुके है। ऐसे में यूएनएचसीआर कार्ड के आधार पर अवैध आप्रवासियों को आधार कार्ड जारी करना 'बेहद अनुचित और गैरकानूनी' होगा। इस संबंध में मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से उन रोहिंग्या शरणार्थियों और अन्य अवैध निवासियों के आंकड़े जुटाकर गृह मंत्रालय को भेजने के लिये कहा है जिनके पास आधार कार्ड है। यह कवायद इसलिए है ताकि ये आंकड़े यूआईडीएआई के साथ साझा किये जा सकें। मंत्रालय यह भी स्पष्ट किया कि इस बात में कोई विवाद नहीं होना चाहिए कि अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों द्वारा धोखे से हासिल किए गये पहचान संबंधी दूसरे दस्तावेज (मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आदि) भी राज्य सरकारें रद्द कर सकती हैं।

अकबर ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को बताया गलत

नई दिल्ली (संवाददाता)।विदेश से लौटने के बाद विदेश राज्यमंत्री एमजे अकबर ने अपने ऊपर लगे यौन

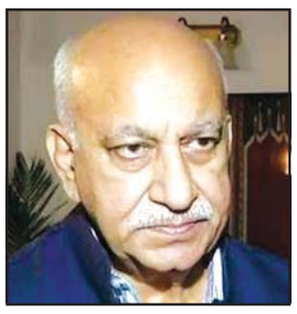

उत्पीड़न के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मुझ पर लगे सभी आरोप गलत और मनगढ़ंत हैं। मेरे खिलाफ लगाए गए दुर्व्यवहार के आरोप झूठे और निराधार हैं। ये आरोप द्वेष भावना से लगाए गए हैं। मैं आधिकारिक टूर पर देश से बाहर था इसलिए पहले जवाब नहीं दे पाया।

उन्होंने कहा कि उनपर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों के खिलाफ वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। आखिर यह मीटू तूफान आम चुनाव के कुछ महीने पहले ही क्यों उठा? क्या ये कोई अजेंडा है? इन झूठे और आधारहीन आरोपों ने मेरी प्रतिष्ठा और सद्भावना को क्षति पहुंचाई है। झूठ के पैर नहीं होते और वह जहरीला भी नहीं होता जिसे आसानी से धोया जा सकता है। अकबर ने कहा कि कुछ तबको में बिना किसी सबूत के आरोप लगाने की बीमारी सी हो गई है। अब मैं वापिस आ गया हूं और आगे क्या कानूनी कार्रवाई की जाए, इसके लिए मेरे वकील योजना तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रिया रमानी ने इस कैंपेन को साल भर पहले एक मैगजीन में आर्टिकल लिखकर शुरू किया था। उन्होंने मेरा नाम तक नहीं लिया क्योंकि वह जानती है कि यह एक मनगढ़ंत कहानी है। जब उनसे हाल में पूछा गया तो उन्होंने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। उन्होंने एक ट्वीट के जवाब में लिखा- उनका नाम कभी नहीं लिया क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था।

अकबर मामला : पीएम की चुप्पी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

केंद्र की मोदी सरकार के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मचे घमासान और उनकी चुप्पी पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खामोशी तोड़ने की मांग की है। रविवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने मीटू कैंपेन के तहत सामने आए एमजे अकबर के खिलाफ यौन शोषण के मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस पर जवाब देते हुए पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। आनंद शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी देशवासियों

को ये बताएं कि वो ऐसे मामलों पर वे अपने ऊपर लगे आरोपों पर बाद में क्या सोचते हैं।

उन्होंने कहा, ये सरकार की मर्यादा का सवाल और पीएम पद की गरिमा का भी सवाल है। देश में इतनी बड़ी बहस चल रही है और देश की जनता व महिलाएं इस पर पीएम मोदी की सोच जानना चाहती है और देश ये भी जानना चाहता है कि आप इस पर क्या करेंगे। रविवार को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर लौटने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि बयान जारी करेंगे।

तकरीबन रोजाना हो रहे नये खुलासों से उनपर केन्द्रीय मंत्री की कुर्सी को छोड़ने का जबर्दस्त दबाव है। भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष के निशाने पर हैं, कई महिला संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मांग की है कि एमजे अकबर को अविलंब पद से हटाया जाए। एमजे अकबर पर अब तक हर उम्र की 11 महिलाएं यौन शोषण, अश्लील हरकत जैसे गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। इनमें विदेशी महिला भी शामिल हैं।

दिल्ली के 400 पेट्रोल पंप 22 से हड़ताल पर

नई दिल्ली(एजेंसी)। दिल्ली सरकार के वैट कम न करने के फैसले के खिलाफ पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल की घोषणा की गई है। दिल्ली के पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने केजरीवाल सरकार के पेट्रोल और डीजल के दामों में वैट कम न करने के फैसले के विरोध में इस हड़ताल का आह्वान किया है. दिल्ली के 400 पेट्रोल पंप 22 अक्टूबर सुबह 6 बजे से 23 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बिक्री बंद रहेंगी।

राहुल का कर्मचारियोंसे मिलना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहितकर : एचएएल

नई दिल्ली (संवाददाता)। राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के पूर्व एवं वर्तमान कर्मचारियों से संपर्क करने को सरकारी क्षेत्र की एयरोस्पेस कंपनी ने राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संस्थान के लिहाज से अहितकर बताया। एचएएल का यह बयान उस घटनाक्रम के बाद आया है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि आधुनिक भारत के संस्थानों पर हमले हो रहे हैं और उन्हें तबाह किया जा रहा है। हालांकि इस बयान में राहुल गांधी के कंपनी के कर्मचारियों से मिलने का खास तौर पर जिक्र नहीं किया गया था।

कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि राजग सरकार ने उसके प्रमुख स्थान को मान्यता देते हुए 2014 से 2018 की अवधि के दौरान करीब 27,340 करोड़ रुपये के आपूर्ति ऑर्डर देकर एचएएल को पूर्ण सहयोग दिया है। अधिकारी ने कहा कि उत्पादन सुविधाएं बढ़ाने सहित अवसंरचना में सुधार एवं उन्नयन के लिए इस अवधि के दौरान 7,800 करोड़ रुपये तक का वित्तपोषण किया गया। अधिकारी ने कहा कि रक्षा एवं एयरोस्पेस उद्योग क्षेत्र में एचएएल को गौरव से देखा जाता है और उसने राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में अत्याधिक योगदान

गुजरात दंगों में 355 का इस्तेमाल क्यों नहीं किया : हामिद अंसारी

नई दिल्ली (संवाददाता)। पूर्व उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह की पुस्तक रुद सरकारी मुसलमानरु के विमोचन के मौके पर 2002 के गुजरात दंगों का उल्लेख करते हुए तत्कालीन सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, जबकि उसके रक्षा मंत्री मौके पर थे। अंसारी ने यह टिप्पणी लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) जमीर उद्दीन शाह की पुस्तक रुद सरकारी मुसलमानरु के विमोचन के मौके पर कही, जिन्होंने सेना की उस डिविजन का नेतृत्व किया था, जिसने गुजरात में दंगों को शांत कराया था। पूर्व उप राष्ट्रपति अंसारी ने कहा कि रुआतंकवाद का कोई सैन्य हलरु नहीं है, क्योंकि सामान्य स्थिति लोगों का दिल और दिमाग जीतकर ही बहाल की जा सकती है। अंसारी ने दंगों पर शाह की पुस्तक की कुछ टिप्पणियों को उद्धृत करते हुए कहा, रुनागरिक प्रशासन की प्रारंभिक प्रतिक्रिया सुस्त थी, कर्फ्यू का आदेश दे दिया गया

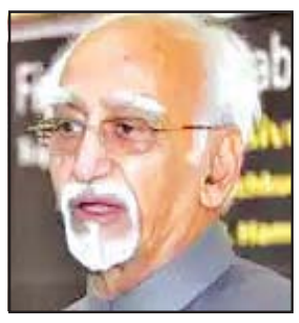

था, लेकिन वह लागू नहीं हुआ था। शांति समितियां आहूत करने का कोई प्रयास नहीं किया गया और पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण था। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, रुयदि नागरिक और पुलिस प्रशासन कानून एवं व्यवस्था को बड़े पैमाने पर विफलता पर प्रतिक्रिया नहीं जताता तो लोकतांत्रिक और संसदीय प्रणाली में जिम्मेदारी कहां है। उन्होंने सवाल किया, रुसंविधान के अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, जबकि केंद्र को यह सुविधा थी कि रक्षा मंत्री मौके पर थे? अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र का यह दायित्व है कि वह आंतरिक अशांति के समय राज्य का संरक्षण करे।

उन्होंने कहा पूर्व राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने 2005 में एक मलयालम साप्ताहिक के साथ साक्षात्कार में सरकार के साथ अपनी आपत्ति का खुलासा किया था, मैं उन्हें (नारायणन को) उद्धृत करता हूं, सेना भेज दी गई थी लेकिन उसे गोली चलाने का अधिकार नहीं दिया गया था और गुजरात दंगों के पीछे केंद्र और राज्य सरकार की संलिप्तता वाला एक षड्यंत्र था। पुस्तक ने एक विवाद उत्पन्न कर दिया है। इसमें आरोप लगाया है कि राज्य में दंगे शुरू होने के बाद अहमदाबाद में पहुंची सेना के लिए परिवहन और अन्य साजोसामान सहायता रुएक दिन बाद पहुंचीरु थी।

बीजेपी ने की सिद्धू को कांग्रेस से निकालने की मांग

नई दिल्ली (संवाददाता)। कांग्रेस नेता और पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह

सिद्धू का एक बार फिर पाकिस्तानी प्रेम जाग उठा है। इस प्रेम को लेकर विरोधी दल भाजपा कांग्रेस पर हमलावार हो गई है। रविवार को बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा रहम जानते हैं कि आप और आपकी पार्टी पाकिस्तान से प्रेम करते हैं। आपकी पार्टी के सदस्य पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सभी दक्षिण भारतीय लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें सिद्धू से भी माफी मंगवानी चाहिए, इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए।

गुरुग्राम गोलीबारी : न्यायाधीश की पत्नी की मौत

हत्यारे को चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा

(एजेंसी)।

गुड़गांव। गुड़गांव के भीड़ - भाड़ वाले एक बाजार में निजी सुरक्षा गार्ड के कथित रूप से गोली मारने के बाद घायल हुई एक न्यायाधीश की पत्नी की मौत हो गई है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कृष्ण कांत की पत्नी रितु (45) और पुत्र ध्रुव (18) शनिवार को आर्केडिया मार्केट में खरीदारी के लिए गये थे। उसी दौरान उनके निजी सुरक्षा गार्ड महिपाल ने उन्हें गोली मार दी। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया।

गुड़गांव सिविल अस्पताल के क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी पवन चौधरी ने रितु की मौत होने की पुष्टि की है और कहा कि उनके शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। चौधरी ने बताया कि उनके पुत्र की हालत गंभीर बनी हुई है।

हत्यारे को चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा

इस बीच, महिपाल को दोपहर एक बजे गुड़गांव की एक अदालत में लाया गया, जिसने उसे चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। जांच टीम से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिपाल लगातार अपने बयान बदल रहा है और सवाल पूछे जाने पर वह गुस्सा हो जाता है। वह अपनी निजी, पारिवारिक समस्या को लेकर अवसाद में है।

पुलिस ने बताया कि गोलीबारी की यह घटना शनिवार को अपराह्न करीब साढ़े तीन बजे हुई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रितु को सीने में और ध्रुव को सिर में गोली लगी थी। आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वह हरियाणा पुलिस का एक हेड कांस्टेबल है और पिछले दो वर्षों से न्यायाधीश के निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात था।

अधिकारियों ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से घर जाने के लिए छुट्टी मांग रहा था जो उसे नहीं दी जा रही थी। इससे शायद वह अवसाद में चला गया। जांच अधिकारियों में से एक ने बताया, ''न्यायाधीश भी अक्सर उसे डांटते थे।'' अधिकारी ने बताया कि शनिवार को भी न्यायाधीश की पत्नी ने बाजार जाते समय कार में उसे डांटा। न्यायाधीश के खिलाफ उसमें काफी असंतोष था।

अमेठी में भीड़ ने दो लोगों की पीट पीटकर हत्या की

अमेठी(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में अमेठी के सरैया गांव में एक मंदिर में धार्मिक समारोह के दौरान 12 साल के लड़के पर कथित तौर पर गोली चलाने वाले दो लोगों की भीड़ ने पीट पीटकर हत्या कर दी।

पुलिस ने रविवार को बताया कि लड़के को गोली मारी गई और उसका एक स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है।

मुसाफिरखाना के थाना प्रभारी विश्वनाथ यादव ने बताया कि शनिवार रात को नशे में धुत्त दिलीप यादव (28) और राहुल सिंह (30) ने सुमित को गोली मारकर घायल कर दिया।

उन्होंने बताया कि मंदिर में पूजा के दौरान यह घटना हुई जिसके बाद भीड़ ने यादव और सिंह की पीट पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि यादव और सिंह पड़ोसी गाजनपुर दुअरिया गांव के रहने वाले थे। उन्हें मुसाफिरखाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

एसएचओ ने बताया कि मृतकों में से एक के भाई की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि गांववालों की शिकायत पर छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

कार्यकर्ताओंको अहंकारी नहीं होना चाहिए : भागवत

बैतूल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के बैतूल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय घोष वर्ग प्रशिक्षण के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा हम अपने आनंद के लिए नहीं वरन विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कई बार अच्छे वादक और गायक को अपने गुण का अहंकार हो जाता है। वह अपने से, लोगों को जोड़ नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को अहंकारी नहीं होना चाहिए।

समापन कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयं सेवक यहां पर आए थे। उनके बीच में मोहन भागवत के अहंकार के मामले में आपसी चर्चा हो रही थी।

बंद कमरे में 20 दिन बाद महिला का मिला शव

नोएडा (एजेंसी)। नोएडा के सेक्टर-99 में सुप्रीम सोसाइटी में 20 दिन से बंद फ्लैट में रविवार को एक महिला का शव मिला है। महिला फ्लैट में अकेली रहती थी। उसका बेटा बेंगलुरू में सोफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों किडनियां खराब होने के चलते महिला की हालत काफी नाजुक थी। 20 दिन से न तो बेटे ने उसकी कोई सुध ली और न ही किसी पड़ोसी ने उसका दरवाजा खटखाया। बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी गई। सेक्टर-39 पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु कर दी है।

मूल रूप से पश्चिम बंगाल के दक्षिणी कोलकाता निवासी बबीता(52) सुप्रीम सोसाइटी के टावर नंबर वन में किराए के फ्लैट में अकेली रहती थीं। उनका 28 वर्षीय बेटा सिद्धार्थ बसु बेंगलरु स्थित एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बबीता की दोनों किडनियां खराब थीं। प्रत्येक हफ्ते दिल्ली के एक अस्पताल में उनका डायलेसिस होता था। पूर्व में बेटा भी कुछ दिन के लिए बीबता को बेंगलुरु साथ लेकर गया था और वहां उनका उपचार कराया था। लेकिन काफी इलाज के बाद भी वह ठीक नहीं हो सकीं। नोएडा में वह खुद ही अपना भोजन बनाने समेत तमाम

घरेलू कामकाज करती थीं।

करीब 20 दिन से उनके फ्लैट का मुख्य द्वार भीतर से बंद था। लेकिन किसी पड़ोसी ने उनका दरवाजा खटखटाने की कोशिश नहीं की। न ही किसी ने पुलिस को सूचना देने की जहमत उठाई। इस दौरान बेटे ने भी यहां आकर मां की सुध नहीं ली। शनिवार से पड़ोसियों को फ्लैट से बदबू आ रही थी। मगर इसके बाद भी लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जब ज्यादा बदबू फैलने लगी तो रविवार सुबह सात बजे एक पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर सूचना दी। मौके पर पहुंची सेक्टर-39 पुलिस गेट तोड़कर फ्लैट में दाखिल हुई। कमरे में बबीता का शव बैड पर पड़ा हुआ था। पुलिस ने फ्लैट से साक्ष्य जुटाए। पुलिस को वहां से मेडिकल कागज मिले हैं। जिसमें पता चला है कि वह किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं। पुलिस ने मामले की सूचना बबीता के बेटे शिद्धार्थ को दी। हवाई सफर से दोपहर तक सिद्धार्थ बेंगलुरु से नोएडा पहुंचा।

एसएचओ अमित कुमार ने बताया कि महिला की मौत बीमारी के चलते हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में कोई लिखित में शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

अंतिम बार सिद्धार्थ की अपनी मां से 19 सितंबर को फोन पर बात हुई थी। सिद्धार्थ ने पुलिस को बताया कि वह 3-4 दिन से अपनी मां के पास फोन लगा रहा था, लेकिन मोबाइल बंद था। तभी से उन्हें अनहोनी की आशंका थी। उन्होंने फ्लैट मालिक को फोन पर संपर्क करने का भी प्रयास किया था।

सोसाइटी में रहने वाली एक महिला ने बताया कि बबीता कभी-कभी उन्हें पार्क में टहते हुए मिल जाती थी। लेकिन वह खुश नहीं रहती थी। हमेशा चेहरे पर मायूसी छाई रहती थी। वह अपनी बीमारी और अकेलेपन के बारे में बताती थीं। काफी बीमार होने के बाद भी उन्होंने कभी किसी पड़ोसी से कोई मदद नहीं मांगी। ज्यादा बाहर नहीं घूमती थीं। 15 साल पहले महिला का तलाक हो गया था।

दिल्ली महिला आयोग ने ''मी-टू'' की शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीएम से भी मांगा समर्थन

नई दिल्ली(एजेंसी)। दिल्ली महिला आयोग ने आधिकारिक बयान जारी कर मी टू अभियान के तहत पीड़ित महिलाओं और लड़कियों की बढ़ती संख्या पर दुख जताते हुए कहा कि, किसी भी महिला के लिए अपने साथ हुए यौन दुर्व्यवहार के बारे में बताने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। ऐसे में दिल्ली महिला आयोग उनके इस संघर्ष में उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। आयोग का यह विश्वास है कि इनके सामने आने से अन्य कई महिलाओं को यौन अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने और अपनी आपबीती बताने का साहस मिला है। इस तरह उन्होंने न केवल अपनी सहायता की है बल्कि यौन अपराधों के खिलाफ जागरूकता भी बढ़ाई है।

दिल्ली महिला आयोग ने आगे अपने बयान में कहा कि, इस अभियान से कई यौन अपराधियों का खुलासा हुआ है और कई महिलाओं का एक ही व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। आयोग ने एमजे अकबर का उदाहरण देते हुए कहा कि, जिसके खिलाफ 8 से ज्यादा महिलाओं ने यौन दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज करवाई है, उन्होंने अपने कॅरियर में ऊंचाईयों को छुआ और यहां तक की केंद्र में मंत्री पद तक पहुंचे। उनको कभी अपने किये का दंड नहीं मिला और जिन महिलाओं का शोषण हुआ वो अभी भी न्याय का इंतज़ार कर रही हैं। आयोग का यह मानना है कि इन अपराधियों को जेल भेजा जाये और इन पर घिनौने अपराधों के लिए मुकदमा चले।

इसलिए आयोग रुडमज्वव की शिकायतकर्ता महिलाओं और लड़कियों से यह अपील करता है कि वो अपने साथ हुए यौन दुर्व्यवहार की शिकायत पुलिस और महिला आयोग में दर्ज करवाएंद्य शिकायत दर्ज करने से इन यौन अपराधियों को जेल भिजवाने का रास्ता साफ होगा जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था।

दिल्ली महिला आयोग ने इन मामलों से सम्बंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए एक अलग से इमेल आईडी बनाई है- उमजववकबू/हउंपस.बवउ, जिस पर शिकायतकर्ता किसी भी सहायता की लिए 181 पर भी फोन कर सकती हैं। दिल्ली महिला आयोग की 181 महिला हेल्पलाइन एक टोल फ्री सेवा है, जिसने पिछले ढाई सालों में 2.35 लाख फोन कॉल पर काम किया हैद्य 181 हेल्पलाइन 24'7 काम करती है।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने प्रधानमन्त्री को लिखे पत्र में उनसे मी टू अभियान को समर्थन देने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कहीं न कहीं हमारे सिस्टम की विफलता से मीटू अभियान का जन्म हुआ है क्योंकि ज्यादातर महिलाओं और लड़कियों का विश्वास इस सिस्टम में कम होता जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने, पुलिस के संसाधन और जवाबदेही बढ़ाने और एक मजबूत न्याय व्यवस्था बनाने की अपील की है।

ईमानदारी से टैक्स चुकाने वालों को मिलेंगी सुविधाएं

नई दिल्ली(एजेंसी)। सरकार ईमानदारी और समय से कर चुकाने वाले नागरिकों को कई तरह की सहूलियतें देने की तैयारी कर रही है। ऐसे करदाताओं को सार्वजनिक सेवाओं में विशेष सुविधा के साथ प्राथमिकता भी दी जाएगी। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया कि यह महात्वाकांक्षी योजना इस साल के अंत तक लागू की जा सकती है।

अधिकारी के अनुसार, आयकर विभाग की नीतियां बनाने वाली शाखा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया है, जो इस तेजी से काम कर रही है। सीबीडीटी और आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की यह टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट बोर्ड को सौंप सकती है। यह समिति समय पर पूरा कर चुकाने वाले नागरिकों का पैमाना तय करेगी और उन्हें दी जाने वाली सहूलियतों की सूची तैयार करेगी।

मसौदा तैयार होने के बाद वित्त मंत्रालय इसका निरीक्षण करेगा और प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुमति मिलने के बाद कैबिनेट में पारित कराने के लिए लाया जाएगा। योजना के तहत ईमानदार करदाताओं को सार्वजनिक सेवाओं का लाभ प्राथमिकता के तौर पर दिलाया जाएगा। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल की शुरुआत में करदाताओं में भरोसा कायम करने और उन्हें ईमानदारी से कर चुकाने को प्रेरित करने के लिए इस तरह की योजना शुरू करने की बात कही थी।

वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि हर साल समय पर लगातार कर चुकाने वाले और रिटर्न दाखिल करने वालों को सभी सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता देने के साथ उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले भी सीबीडीटी ने मेहनती करदाताओं को प्रशंसा पत्र भेजने की शुरुआत की थी, जिसमें सीबीडीटी चेयरमैन के हस्ताक्षर अंकित होते थे।

सरकार ईमानदार और समय पर कर चुकाने वाले नागरिकों को उनकी पहचान के लिए 'यूनिक आईडेन्टिटी नंबर' जारी कर सकती है। इसके अलावा ऐसे करदाताओं के परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को विशेष सेवाओं के साथ जोड़ सकती है, जिसके बाद वे सरकार की ओर से मिलने वाली विशेष सहूलियतों का लाभ ले सकेंगे।

सरकार ऐसे करदाताओं को एयरपोर्ट चेकइन करने में छूट दे सकती है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर लाउंज की सुविधा लेने में भी सहूलियत दी जा सकती है। ऐसे करदाता पासपोर्ट बनवाने में भी प्राथमिकता पाने के योग्य होंगे और डेडीकेटेड टोल लेन में छूट देने के बारे में विचार किया जा रहा है।

सरकार ने केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए कैबिनेट नोट भेजा है, जिसके तहत टैक्स भरने और आईटीआर दाखिल करने का डाटा तेजी से संग्रहित किया जा सकेगा। इससे रियल टाइम में गणना कर आईटीआर दाखिल करने वालों को महज कुछ घंटों में रिफंड दिया जाएगा। इसके अलावा करदाता देश में कहीं से भी आकलन कर सकेंगे।

संपादकीय

दवा का दर्द

तरह-तरह की बीमारियों के अंधेरे में वह साल एक सूर्योदय की तरह था। यह ठीक है कि 75 साल पहले जिन एंटीबायोटिक का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ, उनके पास सभी बीमारियों का इलाज नहीं था, लेकिन दुनिया की बहुत सी महामारियों के लिए वे रामबाण की तरह थीं। इसने मानवता को प्लेग जैसी महामारी से मुक्ति दिलाई, जिसके आतंक से यह खौफ पैदा हो गया था कि कहीं यह पूरी दुनिया की मानव आबादी को ही न निगल जाए। वर्ष 1340 में जब यह बीमारी यूरोप पहुंची, तो वहां इसने एक साल में ही ढाई करोड़ लोगों की जान ले ली थी। ऐसी बीमारियों की सूची बहुत लंबी है, जिनका रामबाण इलाज एंटीबायोटिक के आगमन के बाद ही संभव हुआ। और प्लेग जैसी बीमारियों का तो लगभग उन्मूलन ही हो गया। आज भले ही एंटीबायोटिक की आलोचना या उसे कोसना फैशन में आ गया हो, लेकिन यह सच है कि उसने अब तक करोड़ों या शायद अरबों लोगों की जान बचाई है। कुछ मामलों या कुछ खास लोगों में इसकी एलर्जी जैसे दुष्प्रभाव भले ही दिख जाएं, लेकिन अभी भी बहुत सी बीमारियों का इलाज सिर्फ इन्हीं के भरोसे किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि ये आसानी से उपलब्ध भी हैं। यही आसानी ही अब समस्या के रूप में सामने आ रही है। समस्या इतनी बड़ी है कि अपनी हीरक जयंती मना रही एंटीबायोटिक अपनी शताब्दी भी मना पाएगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। समस्या दो स्तरों पर है। आसानी से उपलब्ध होने के कारण इनका इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा और बहुत ज्यादा होने लगा है। इस वजह से शहरों में ही नहीं, गांवों और यहां तक कि जंगलों में भी जब दूध, पानी, शहद या किसी भी प्राकृतिक चीज के नमूने लिए जाते हैं, तो उनमें एंटीबायोटिक के अवशेष मिल जाते हैं। इस वजह से एक तो तरह-तरह केकीटाणु एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोध विकसित करते जा रहे हैं। यानी उन पर अब बहुत से एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। पहले आमतौर पर यह होता था कि कीटाणु एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोध विकसित कर लेते थे, उनके इलाज के लिए नई एंटीबायोटिक बाजार में आ जाती थी। लेकिन अब इस मामले में एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई है। एक तो कुछ कीटाणु ऐसे हो गए हैं, जो सुपरबग कहलाने लगे हैं, उन पर किसी भी एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। दूसरी समस्या यह है कि नई एंटीबायोटिक खोजने का काम मंदा पड़ गया है। किसी भी नई एंटीबायोटिक को खोजने और सारे परीक्षण करके बाजार में उतारने में दो दशक या उससे ज्यादा समय लग जाता है। इसमें इतना ज्यादा निवेश होता है कि शुरुआत में उनकी कीमत बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से वे कम बिकती हैं, कंपनियों को घाटा होता है और जब तक उनके बड़े स्तर पर बिकने का मौका आता है, कीटाणु उनका प्रतिरोध विकसित कर चुके होते हैं। तमाम बड़ी दवा कंपनियों ने नई एंटीबायोटिक विकसित करने से अपना हाथ खींच लिया है। यह काम अब कुछ छोटी कंपनियां ही कर रही हैं। यह भी कहा जाता है कि यह समस्या एंटीबायोटिक की नहीं, बाजार की पैदा की हुई है। तमाम बीमारियों का इलाज करने वाली एटीबायोटिक के पास बाजार की इस समस्या का कोई इलाज नहीं। पर यह भी सच है कि हमारे पास एंटीबायोटिक का अभी कोई विकल्प नहीं है। जब तक नहीं है, हमें उसके सौ नहीं दो सौ साल जीने का इंतजाम करना होगा।.

सुप्रीम न्याय

सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करने का आदेश देकर साफ कर दिया है कि कोई भी सरकार या विभाग किसी व्यक्ति को इस आधार पर नौकरी से वंचित नहीं कर सकता कि उसके खिलाफ कभी अपराध का मुकदमा चला था। लोकसेवा आयोग ने न्यायिक सेवा में चयन के बावजूद मो. इमरान को न्यायाधीश बनने के योग्य नहीं माना था, क्योंकि उस पर 21 वर्ष की उम्र में एक लड़की के अपहरण का आरोप लगा था। न्यायालय की चार सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि प्रतिभाशाली शख्स को सिर्फ इस आधार पर न्यायाधीश की पदवी से वंचित नहीं किया जा सकता कि कभी उसके दामन पर काले छींटे पड़े थे। इमरान ने 2009 में न्यायिक सेवा की परीक्षा पास कर ली थी। कायदे से उसकी नियुक्ति उसी वर्ष हो जानी चाहिए थी किंतु उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत हुआ मुकदमा आड़े आ गया, जबकि उसने इसे बरी होने का पूरा ब्योरा लोक सेवा आयोग को दिया था। हालांकि एक अन्य अभ्यर्थी पर भी धारा 294 और 504 के तहत सार्वजनिक स्थल पर अश्लील हरकतें करने और धमकी देने का मुकदमा चला था। मगर वह बरी हो गया था। आयोग ने उसको तो नियुक्त कर लिया लेकिन इमरान को न्यायिक सेवा के काबिल नहीं समझा। ठीक है कि न्यायाधीश का पद अन्य नौकरियों से भिन्न है। यहां नैतिक आचरण का पैमाना अन्य सेवाओं से ज्यादा उच्च स्तर का होना चाहिए। लेकिन नैतिकता का पैमाना सबके लिए एक ही होना चाहिए। वैसे भी कोई बरी हो गया तो उसे अपराधी कैसे माना जा सकता है? किसी भी सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद नियुक्ति के पूर्व पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस ने यदि रिपोर्ट में संदेह का प्रश्न खड़ा कर दिया तो नियुक्ति बाधित हो जाती है। न्यायालय ने मामले की पूरी समीक्षा के बाद ही नियुक्ति को हरी झंडी दी है। इसका अर्थ हुआ कि पुलिस की रिपोर्ट एवं आयोग का निर्णय दोनों न्याय की कसौटी पर खरे उतरने वाले नहीं थे। उत्तीर्णता के बावजूद किसी को इस आधार पर नियुक्त न किया जाए कि उस पर कभी कोई मुकदमा हुआ था तो यह उसकी मेहनत तथा प्रतिभा का अपमान है। उम्मीद करनी चाहिए कि न्यायालय का फैसला नजीर बनेगा और आगे नियोक्ता संस्थाएं इस तरह का निर्णय नहीं करेंगी।

परिधि/ विशाल तिवारी

'ठांय-ठांय' से खुली पोल

उत्तर प्रदेश और बिहार में अपराधियों का बोलबाला किसी कदर है, यह किसी से छुपा नहीं है। आए दिन होने वाली वारदात और आंकड़े इसकी गवाह भी देते हैं। इन राज्यों में अपराध और खस्ताहाल कानून-व्यवस्था को लेकर सरकारें तक बनती-बिगड़ती रहीं हैं। यही वजह है कि अपराधियों के खात्मे को लेकर कई बार सरकार ने हदें भी पार की है। विशेषकर उ.प्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो पुलिस को इन्हें ''ठोक' देने की खुली छूट दे रखी है। मगर हाल की दो घटनाएं पुलिस की खुद की हिफाजत को लेकर सवाल भी उठाती है। पहली घटना बिहार के खगड़िया जिले से जुड़ी हुई है, जहा अपराधियों के साथ मुठभेड़ में पसराहा थाना के प्रभारी आशीष कुमार की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना उ.प्र के संभल जिले में अपराधियों से मुठभेड़ के दौरान हुई। यहां ऐन मौके पर दरोगा मनोज कुमार की रिवॉल्वर दगा दे गई, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए मुंह से गोली चलने की आवाज निकालकर अपराधियों को भ्रम में रखा। मनोज कुमार तो अपनी बुद्धिमत्ता से बच गए, मगर ऐसे मौके किस्मत से ही मिलते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लोग भले हंसी-ठिठोली के तौर पर लें, मगर 20 मार्च से 31 दिसम्बर 2017 के बीच के उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान उ.प्र में 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जबकि 210 घायल हुए। आंकड़े पुलिस द्वारा खुद की सुरक्षा में खामी की ओर इशारा करते हैं। अगर हथियार ही दुरूस्त नहीं होंगे तो आप अपराधियों को ''ठोंकने' का दम कैसे भर रहे हैं? हथियार का सीधा संबंध पुलिस बल के आत्मविास से होता है। वहीं पुलिस जिन अपराधियों से लोहा ले रही है, वो कट्टे वाले अपराधी नहीं हैं। साथ ही समुचित संख्या में बचाव के उपकरण भी पुलिसबल के पास नहीं हैं। आबादी के अनुपात में पुलिस की संख्या को भी दुरूस्त करना होगा, जिससे उनपर काम का दबाव कम हो, और कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर अच्छे नतीजे आ सकें। आज भी पुलिस सुधार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर राज्य सरकारें कान देने को राजी नहीं। अगर पुलिस सुधार पूर्ण रूप से लागू हो गए तो पुलिस के साथ इन राज्यों का भी कायाकल्प हो जाएगा। क्योंकि विकास का सीधा संबंध कानून-व्यवस्था से होता है।

रिपोर्ट को नहीं अपने धुएं को देखें

अनिल पी जोशी

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की रिपोर्ट उस समय आई है, जब हमारे सिर पर कई खतरे मंडरा रहे हैं। दिल्ली का बढ़ता वायु प्रदूषण फिर एक बार हमारी नीतियों पर सवाल खड़े कर रहा है। हरियाणा, पंजाब की पराली का धुआं फिर पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का गला घोंटने को तैयार है। पराली को जलाने की बजाय अन्य उपयोगों में लाने की कवायद असफल होती दिख रही है। इसके लिए बनी केंद्र सरकार की 1,000 करोड़ रुपये की योजनाएं भी शायद स्वाहा हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों राज्यों में किसान पराली जलाने के विकल्प के अभाव का रोना रो रहे हैं। उनके अनुसार, सरकार द्वारा पोषित पराली प्रबंधन मशीन ज्यादा लाभदायक सिद्ध नहीं हुई। साथ ही कुछ जगह यह नारा भी सामने आया है- किसान दी मजबूरी है, नर्द (पराली) नू अग्ग जरूरी है। कहा जा रहा है कि पराली जलाने का जुर्माना उसके अन्य उपयोग में लाने वाले खर्च से सस्ता है।

बेशक आईपीसीसी की रिपोर्ट का पराली जलाने और दिल्ली के प्रदूषण से कोई सीधा नाता नहीं, लेकिन इसमें हम उन चिंताओं का कारण देख सकते हैं, जो रिपोर्ट में व्यक्त की गई हैं। इस रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि तमाम संकल्पों के बाद भी हम सुधार लाने की कोशिशें करने में पूरी तरह असफल हैं। रपट के अनुसार, धरती का मौजूदा औसत तापमान 1.5 या 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा। इसे अगर तत्काल गंभीरता से नहीं लिया गया, तो 2030 तक दुनिया गंभीर संकट में पड़ जाएगी।

दुनिया भर के 40 देशों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई 400 पन्नों की इस रिपोर्ट के अनुसार, हम इतने गंभीर संकट में फंसे होंगे, जहां से वापसी संभव नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को कतई भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पिछली गरमी और बरसात ने कुछ ऐसे ही प्रमाण दिए हैं, जो इस रिपोर्ट की प्रामाणिकता को बताते हैं। एशिया महाद्वीप में तूफान और बाढ़ का उन जगहों पर प्रकोप, जहां इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, इसी परिवर्तन का हिस्सा हैं। इस रपट के अनुसार, बढ़ते तापक्रम के कारण हिमखंड तेजी से पिघलेंगे ही, जिससे समुद्र के जल-स्तर के बढ़ने की आशंका के साथ ध्रुवीय भालू, ह्वेल, सील व समुद्री पक्षियों के आवास को सीधा खतरा झेलना पड़ेगा। और अगर यह तापमान 2 डिग्री तक बढ़ा, तो गरमियों में बर्फ 10 गुना तेजी से पिघलकर एक बड़ी तबाही पैदा कर देगी।

सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत, पाकिस्तान और एशिया इसका बड़ा शिकार बनेंगे। अगर तापमान 1.5 डिग्री बढ़ा, तो दुनिया की करीब 14 फीसदी आबादी भीषण गरमी झेलेगी और इसकी वृद्धि 2 डिग्री हुई, तो 37 फीसदी आबादी पर गाज गिरेगी। इसका एक असर जल की उपलब्धता पर पड़ेगा, जिससे दुनिया का

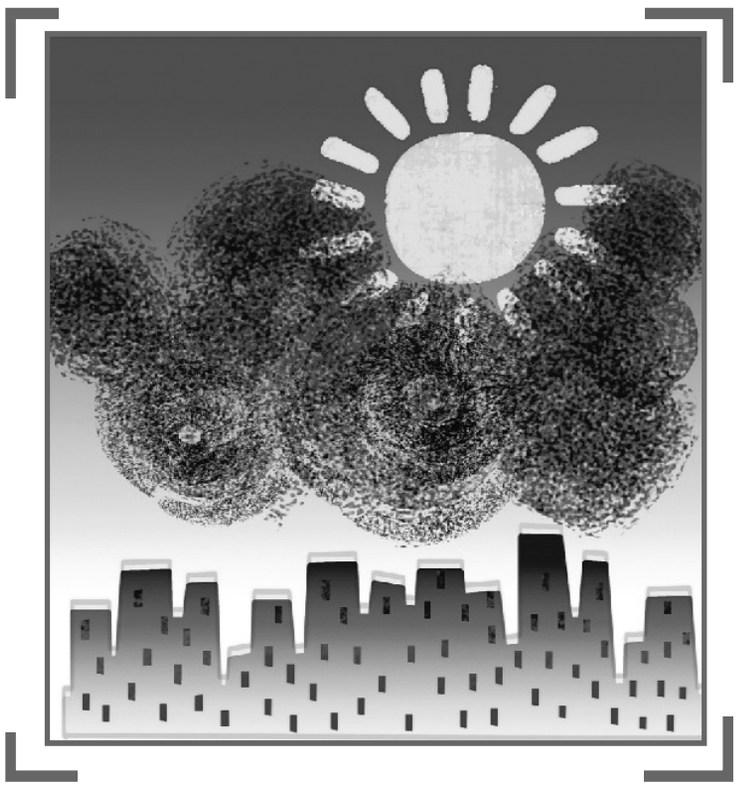

भूमध्यरेखीय क्षेत्र सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और करीब 411 करोड़ से अधिक शहरी आबादी को बड़े जल संकट से जूझना पड़ेगा। दुनिया भर की तमाम प्रजातियों की संख्या में बड़ी कमी आ जाएगी, जिनमें छह फीसदी कीट प्रजाति, 18 फीसदी पादप प्रजाति और चार फीसदी जीवों की संख्या आधी रह जाएगी। ये सारी स्थितियां दुनिया में खाद्य संकट पैदा कर देंगी।

भारत की स्थिति और गंभीर है, जहां जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को कभी अधिक गंभीरता से नहीं लिया गया, बस इसके लिए खानापूर्ति की जाती रही। यहां दो चुनौतियां एक साथ हैं। एक तरफ विकास की अंधी दौड़ और दूसरी तरफ अज्ञानतावश उठाए गए कदम, दोनों ही घातक सिद्ध हो रहे हैं। ब्रिटेन की संस्था 'कार्बन ब्रीफ' के अनुसार, पिछले 150 वर्षों में दिल्ली का तापमान एक डिग्री सेल्सियस, मुंबई का 0.7 डिग्री, चेन्नई का 0.6 डिग्री व कोलकाता का 1.2 डिग्री बढ़ा है। लेकिन ये चारों ही महानगर इसके प्रति कितने संवेदनशील हैं, इससे हम सब परिचित हैं। एक बात साफ है कि जलवायु परिवर्तन का बड़ा असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि यहां एक तरफ 9,000 ग्लेशियरों पर घातक असर पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ देश के 7,000 किलोमीटर से ज्यादा समुद्री सीमा तमाम तरह की नई परेशानियां खड़ी करेगी। अपने देश में समुद्र और हिमालय के बीच एक प्राकृतिक तारतम्यता है, जिस पर बढ़ते तापकम के कारण चोट पहुंचेगी और इन दोनों के बीच पलते जीवन को पर्यावरणीय जोखिम से गुजरना पड़ेगा।

पिछले कुछ समय में कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों, चाहे वे विश्व स्वास्थ्य संगठन की हों या फिर किसी अन्य संस्था की, सबने हमें चेताने की कोशिश की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वायु प्रदूषण की रपट पहले ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दूषित देशों में भारत को शामिल कर चुकी है। ऐसे में, अपने देश को अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखानी ही होगी, वरना यह विकासशील देश अपना संतुलन खो देगा। जलवायु परिवर्तन जैसा बड़ा मुद्दा जहां एक तरफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहसों में कलाबाजियां खाता रहता है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर देश भी इसे आत्मसात नहीं करते। मतलब साफ है कि नई दिल्ली का प्रदूषण न्यूयॉर्क में बहस करने से नहीं निपटने वाला और न ही कोलकाता के औसतन तापमान को क्योटो प्रोटोकॉल से नियंत्रित किया जा सकेगा। अपने को अगर बचाना हो, तो सबसे सुरक्षित जगह अपना ही घर ही होता है। इसलिए दुनिया की बहस में उलझने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपने देश में इस दिशा में कारगार कदम उठाए जाएं। संयुक्त राष्ट्र अंतर-सरकारी पैनल की रपट चुनिंदा आंकड़ों और सर्वेक्षणों पर आधारित है, पर अगर अपने देश में गंभीरता से आकलन कर लें, तो स्थिति ज्यादा भयावह दिखाई देगी। ऐसे में, अगर सवाल जान पर बन आने का हो, तो जहान के बीच में बहस पर पड़ने की जरूरत नहीं। शायद हमारी अपनी पर्यावरणीय अंतरिम रिपोर्ट हमें सही आईना दिखा देगी। औरों के लिए वर्ष 2030 या 2050 संकट आने का समय होगा, पर उससे भी जल्दी हम अपने को काल की भेंट चढ़ा देंगे। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

> संयुक्त राष्ट्र पैनल की रिपोर्ट भले ही आईना दिखा रही हो, लेकिन दिल्ली और आसपास फैल रहे धुएं से हम समस्या को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं।

अंतर्मन

दान से घटता नहीं, बढ़ता है धन

रतन चंद 'रत्नेश'

एक पुत्री के पिता बनने पर फेसबुक के सी.ई.ओ. मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक में अपनी हिस्सेदारी का 99 प्रतिशत यानी कि लगभग 3 लाख करोड़ दान करने की घोषणा की थी। साथ ही फेसबुक पर अपनी बेटी के नाम पत्र लिखा कि दुनिया में आने वाले हर शख्स का जीवन बेहतर बनाने के लिए कुछ करना आज के समाज का दायित्व है।

जकरबर्ग द्वारा किया गया दान आज उन्हें विश्व के अन्य सभी बड़े दानियों से कहीं आगे ले जाता है। अब तक तीन सबसे बड़े दानी सऊदी प्रिंस अलसौद (2.11 लाख करोड़), बिल गेट्स (1.84 लाख करोड़) और बारेन बफेट (1.32 लाख करोड़ रुपए) रहे हैं। भारत में ऐसे कई उद्योगपति हैं जो लाखों में दान देते आ रहे हैं। वैसे आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में दानवीरों की संख्या पहले की तुलना में घट रही है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के मुताबिक हमारा देश 2014 की तुलना में 93वें स्थान से फिसलकर 106वें स्थान पर आ गया है। दरअसल दान को हर धर्म में महान मानव धर्म के रूप में देखा जाता है और हमारी भारतीय संस्कृति की तो यह प्राचीन परंपरा रही है, जिसे आज पूरे विश्व में मान्यता मिल रही है। हमारी संस्कृति में सिर्फ धन का दान ही नहीं, बल्कि रक्तदान, देश के लिए बलिदान, क्षमादान, ज्ञानदान, आत्मदान, गोदान, अन्नदान, कन्यादान आदि का भी विशेष महत्व रहा है। सफल मानव जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव-धर्मशास्त्र के उद्भावक राजर्षि मनु ने चारों युगों के चार साधन बताएं हैं—

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते।
द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे।।

अर्थात सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ

और कलियुग में एकमात्र दान मनुष्य के कल्याण का साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है-प्रगट चारि पद धर्म के कलि महुं एक प्रधान, जेन केन बिधि दीन्हें दान करई कल्यान।

क्या कारण है कि आज विश्वभर में दानवीरों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? दरअसल जीवन में सच्ची सफलता पाने के नियमों में यह भी शुमार है। वैकल्पिक चिकित्सा के पुरोधा और मोटिवेटर डा. दीपक चोपड़ा सफलता के सात आध्यात्मिक नियमों में से दान को दूसरे स्थान पर रखते हुए कहते हैं कि दान को हम लेनदेन का नियम भी कह सकते हैं क्योंकि पूरा ब्रह्मांड गतिशील विनिमय पर ही आधारित है। धन के लिए एक अन्य शब्द करेंसी का प्रयोग भी होता है जो कि ऊर्जा को दर्शाता है। करेंसी शब्द लेटिन के 'करेर' से बना है, जिसका अर्थ चलते रहना यानी प्रवाह है। अतः यदि हम धन के प्रवाह को रोकते हैं या उसे जमा करके रखने की सोचते हैं तो उसका प्रवाह हमारे जीवन में भी रुकने लगेगा क्योंकि वह जीवन-ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। उस ऊर्जा को वापिस पास लाने के लिए हमें उसे प्रवाहित करते रहना होगा।

हमारे महान धर्मग्रंथों में दान पर विशेष बल दिया गया है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, 'यदुश्रेष्ठ, सभी पापों को नाश करने वाले, मंगलप्रद, पवित्र अन्य दानों को आप मुझसे कहें।' इस पर भगवान बोले, 'राजन! आप सबसे पहले दस महादानों के विषय में सुनें। उनमें से पहला दान है—कालपुरुष दान, दूसरा है सप्तसागर दान। इसी प्रकार महाभूतघट दान, शैया दान, आत्मप्रतिकृति दान, सुवर्णाश्व दान, सुवर्णाश्वरथ दान, कृष्णाजिन दान, विश्वचक्र दान तथा हमगजरथ दान। ये दस महादान हैं। नृपश्रेष्ठ! आप अन्य लोगों को भी दान-कर्म में प्रेरित करें। देने वाले व्यक्ति का धन घटता नहीं है, अपितु देने से बढ़ता ही रहता है।'

पितामह भीष्म ने भी धर्मराज युधिष्ठिर को दान-धर्म का उपदेश देते हुए कहा था, 'दरिद्रान भर कौन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे धनं अर्थात हे कुंतीपुत्र! जो सर्वसाधनहीन विपन्न व्यक्ति हैं, उसका भरण-पोषण करो। उन असहाय मनुष्यों को अन्न-वस्त्र-भूमि-भवन आदि देकर समाज में उत्तम जीवन धारण करने योग्य बनाओ। दान तभी करना चाहिए जब इसकी इच्छा स्वत- हो। तैत्तिरीयोपनिषद में भी लिखित है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार उदारतापूर्वक देना चाहिए। किसी वस्तु को देने पर यह महसूस हो कि आपने कुछ खो दिया है तो उस देने का कोई अर्थ नहीं। बुझे मन से दिये दान का कोई लाभ नहीं।

गीता में भगवान ने तीन प्रकार के दानों का वर्णन किया है। देश काल और पात्र को ध्यान में रखते हुए प्रत्युपकार न करने वाले व्यक्ति को निःस्वार्थ भाव से जो दान किया जाता है, वह दान सात्विक दान कहा गया है। जो दान क्लेशपूर्वक, प्रत्युपकार के प्रयोजन से फल को दृष्टि में रखकर दिए जाते हैं, उन दानों को राजस दान कहा गया है तथा जो दान बिना श्रद्धा के असत्कारपूर्वक अथवा तिरस्कारपूर्वक अयोग्य देश—काल में कुपात्र के प्रति दिया जाता है, उस दान को तामस कहा गया है। दान यदि गुप्त हो, ऐसा कि दायें हाथ से दिया गया दान बायें हाथ को न मालूम हो तो यह दान अति उत्तम और महादान कहा जाता है।

गिर के शेर

खतरा समझने में ही समझदारी

जाहिद खान

गुजरात के गिर अभयारण्य में पिछले तीन हफ्तों में एक-के-बाद एक 23 शेरों की रहस्यमय ढंग से हुई मौत, ने वन्य प्राणियों के चाहने वालों को हिलाकर रख दिया है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि जंगल के इस राजा को किसकी नजर लग गई है? मरने वाले ज्यादातर शेर, अमरेली जिले के गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क के पूर्वी हिस्से डालखानिया रेंज के हैं। ये शेर क्यों मर रहे हैं, इसके बारे में पहले तो राज्य का वन महकमा चुप्पी साधे रहा। लेकिन जब खबर मीडिया के जरिए पूरे देश में फैली, तब वन महकमे के आला अफसर जागे। स्पष्टीकरण भी ऐसा जिस पर कि शायद ही किसी को यकीन हो। प्रदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक का दावा है कि डालखानिया रेंज में बाहरी शेरों के घुसने से हुई वर्चस्व की लड़ाई यानी ''इनफाइट' में इन शेरों की मौत हुई है। वहीं गुजरात सरकार को भी नहीं लगता कि शेरों की मौत के लिए किसी तरह का वायरस या दीगर वजह जिम्मेदार है। सवाल उठाया जा सकता है कि इतने बड़े जंगल के केवल एक ही हिस्से में इतने बड़े पैमाने पर इनफाइट क्यों हो रही है? गुजरात सरकार और राज्य का वन महकमा, दोनों ही कहीं इन शेरों की मौत की असल वजह को छिपा तो नहीं रहा। इस बीच ये मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने हाल ही में सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को इस पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया है। एशियाई शेरों की मौत की असल वजह भले ही गुजरात सरकार और राज्य का वन महकमा दोनों छिपा रहा हो, लेकिन जिस तरह से इन शेरों की मौत हुई है, उससे यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं इन शेरों की मौत सीडीवी वायरस (केनाइन डिस्टेंपर वायरस) और विनेशिया प्रोटोजोआ वायरस से तो नहीं हुई है। सीडीवी वायरस, वही खतरनाक वायरस है, जिससे प्रभावित होकर तंजानिया (अफ्रीका) के ''सेरेंगेटी रिजर्व फॉरेस्ट' में साल 1994 के दौरान एक हजार शेर मर गए थे। ''गिर के शेरों को भी सीडीवी वायरस प्रभावित कर सकता है', इस बारे में तमाम वन्य जीव विशेषज्ञ साल 2011 से लगातार गुजरात के वन महकमे को आगाह कर रहे हैं। पर राज्य के वन महकमे ने इससे निपटने के लिए कोई माकूल बंदोबस्त नहीं किए। जिसका नतीजा यह निकला कि 23 शेर मौत के मुंह में समा गए और यह खतरा अभी भी टला नहीं है। यदि वायरस फैला तो गिर में और भी शेरों को नुकसान पहुंच सकता है। सिंहों की यह दुर्लभ प्रजाति विलुप्त तक हो सकती है। दुनिया भर में एशियाई शेरों का अंतिम रहवास माने जाने वाले गिर के जंगलों में फिलहाल शेरों की संख्या तकरीबन छह सौ के आसपास होगी। साल 2015 में हुई पांच वर्षीय ''सिंह' गणना के मुताबिक यहां शेरों की कुल संख्या 523 थी। एशियाई शेरों की दुर्लभ प्रजाति पर मंडराते खतरे को देखते हुए, इन शेरों का संरक्षण भी बेहद जरूरी हो गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने आज से तीस साल पहले एक शोध किया था और उसमें बताया था कि एशियाई शेरों में ''इनब्रीडिंग' के चलते अनुवांशिक बीमारी हो सकती है। अगर ये बीमारी हुई, तो इन शेरों की मौत हो जाएगी और उसके चलते एशिया से शेरों का अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। बीमारी से आहिस्ता-आहिस्ता लेकिन कम समय में ये सभी शेर मारे जा सकते हैं। यही वह आशंका थी, जिसकी वजह से वन्यजीव संस्थान ने सरकार को इन शेरों में से कुछ शेरों को किसी दूसरे जंगल में स्थानांतरित करने की योजना बनाकर दी। संस्थान का मानना था कि इनब्रीडिंग के चलते अगर एक जगह किसी बीमारी से शेरों की नस्ल नष्ट हो जाती है, तो दूसरी जगह के शेर अपनी नस्ल और अस्तित्व को बचा लेंगे। कमोबेश यही बात, गुजरात के एक जीव विज्ञानी रवि चेल्लम ने भी की थी। साल 1993 में सौराष्ट्र विविद्यालय से ''एशियाई शेरों का पारिस्थितिकी तंत्र' विषय पर शोध करने वाले चेल्लम ने बतलाया था कि दुर्लभ प्रजाति के इन शेरों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें किसी और जगह पर भी बसाना जरूरी है। बहरहाल, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की सलाह और एशियाई शेरों पर हुए शोध के आधार पर भारतीय वन्यजीव संस्थान ने साल 1993-94 में पूरे देश में सव्रेक्षण के बाद कुछ शेरों को मध्य प्रदेश के कूनो-पालपुर अभयारण्य में शिफ्ट करने की योजना बनाई। लेकिन गुजरात सरकार को यह सीधी-साधी बात समझ में नहीं आई और वो अपने शेर न देने पर अड़ गई। गुजरात सरकार की हठधर्मिता का ही नतीजा था कि मध्य प्रदेश सरकार को अदालत का रुख करना पड़ा। गुजरात सरकार के अड़ियल रवैये और तमाम बेतुकी दलीलों के बावजूद हकीकत यह है कि पिछले ढाई साल में 200 से ज्यादा शेरों की मौत हो चुकी है। इनमें कई मौतें अप्राकृतिक हैं। यह बात समझनी होगी कि एशियाई शेर जिद से नहीं, बल्कि जज्बे से बचेंगे।

सार समाचार

तुर्की में सडक़ हादसे में 22 अवैध प्रवासियों की मौत

अंकारा। तुर्की के पश्चिमी प्रांत इजमिर में रविवार को एक ट्रक पलटने से उसमें सवार 22 अवैध प्रवासियों की मौत हो गयी और 13 अन्य घायल हो गये। संवाद समिति अनादोलू ने बताया कि मारे गये प्रवासियों की नागरिकता का पता नहीं चल सका है। हताहतों में एक गर्भवती महिला और चार बच्चे भी शामिल है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संवाद समिति ने बताया कि ट्रक अयदिन इलाके से इजमिर की तरफ जा रहा था। चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गयी है। गौरतलब है कि वर्ष 2011 में सीरिया में प्रारंभ हुए युद्ध के बाद से तुर्की अस्थायी प्रवासियों के लिए यूरोप में दाखिल होने का मुख्य मार्ग बन चुका है।

गाजा पट्टी पर हमले के बाद, नेतन्याहू ने हमास पर हमला करने की धमकी दी

यरूशलम। गाजा पट्टी से लगी सीमा पर हिंसा की ताजा घटनाओं के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को हमास को धमकी दी कि उसे ''बहुत कठोर प्रहार'' सहना होगा। नेतन्याहू ने साप्ताहिक मंत्रिमंडल बैठक के दौरान कहा, ''वस्तुत- हमास ने संदेश नहीं समझा है। अगर हमले नहीं रुके तो उन्हें दूसरे तरीके से रोका जाएगा, बहुत बहुत कठोर प्रहार की शक्ल में।'' इजराइली प्रधानमंत्री ने कहा, ''हम एक दूसरी तरह की कार्रवाई के बहुत नजदीक है जिसमें बहुत ही कठोर प्रहार शामिल है। अगर हमास अक्लमंद हैं तो यह अब गोलीबारी और हिंसा रोक देगा।'' इजराइल ने शुक्रवार को गाजा पट्टी में ईंधन की आपूर्ति रोक दी।

सऊदी निवेश सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे जेपी मोर्गन और फोर्ड के अधिकारी

वॉशिंगटन। सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी के लापता होने की पृष्ठभूमि में जेपी मोर्गन के सीईओ जेम्स डाइमन और फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रियाद में आयोजित होने वाले एक बड़े निवेश सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया है। सीएनबीसी ने यह खबर दी। वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखने वाले अमेरिका के स्थायी निवासी खशोगी दो अक्टूबर को इस्तांबुल स्थित सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में प्रवेश करने के बाद से लापता हैं। अपनी लेखनी में वह लगातार सऊदी के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की आलोचना कर रहे थे। रियाद में अगले सप्ताह होने वाले 'फ्यूचर इंवेस्टमेंट इनिशिएटिव' से हटने का फैसला लेने वालों में डाइमन और फोर्ड का नाम भी जुड़ गया है। ब्रिटिश उद्योगपति रिचर्ड ब्रैन्सन और उबर के सीईओ डारा खोस्रोशाही, मीडिया कंपनियां ब्लूमबर्ग और सीएनएन ने भी इस सम्मेलन का हिस्सा नहीं बनने का फैसला लिया है। तुर्की के अधिकारियों का कहना है कि उनका मानना है कि खशोगी की सऊदी दूतावास के भीतर हत्या कर दी गई। वहीं सऊदी का दावा है कि वह दूतावास की इमारत से सुरक्षित बाहर निकल गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खशोगी की हत्या होने का तथ्य सच निकलने पर सऊदी अरब को ''कड़ी सजा'' की धमकी दी है। वहीं रियाद ने भी किसी भी दंडात्मक कार्रवाई का खुलकर जवाब देने की बात कही है।

पाक उपचुनाव: इमरान की पार्टी को लगा बड़ा झटका, पीएमएल-एन ने कई सीटों पर दी पटकनी

इस्लामाबाद (एजेंसी)।

पाकिस्तान में हुए उपचुनावों में प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी 'तहरीक ए इन्साफ' को झटका लगा है, वहीं नेशनल असेंबली में अपनी सदस्य संख्या बढ़ाते हुए, अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पीएमएल-एन की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन ने पांच और संसदीय सीटें अपने कब्जे में कर ली हैं. पाकिस्तान में रविवार को पंजाब में नेशनल असेंबली की नौ सीटों, सिंध में एक सीट, खैबर पख्तूनख्वा की एक सीट के लिए तथा 24 प्रांतीय असेंबली सीटों के लिए उप चुनाव हुए. इन 24 प्रांतीय असेंबली सीटों में से 11 सीटें पंजाब प्रांत में, नौ खैबर पख्तूनख्वा में, दो सिंध में और दो बलूचिस्तान में हैं.

जिन सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उनमें से ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जिनसे, 25 जुलाई को हुए आम चुनावों में एक से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कराने वाले उम्मीदवारों ने बाद में इस्तीफा दे दिया था. इस्तीफा देने वालों में प्रधानमंत्री इमरान खान शामिल हैं जिन्होंने नेशनल असेंबली की पांच सीटों से चुनाव लड़ा और पांचों सीटों पर जीते थे.

उपचुनाव में इमरान की पार्टी, उनकी छोड़ी गई दो सीटों पर हार गई. उनकी एक सीट लाहौर (एनए-131) है जहां से पूर्व रेल मंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाज (पीएमएल-एन) के नेता ख्वाजा साद रफीक़ ने जीत हासिल की है. बन्नू सीट से मुत्ताहिदा मजलिस ए अमल (एमएमए) के जाहिद अकरम दुर्रानी ने पीटीआई के नसीम अली शाह को हराया. पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी 25 जुलाई को हुए चुनाव में दो सीटों से हार गए थे.

उपचुनाव में उन्होंने एनए-124 लाहौर में लगभग एकतरफा मुकाबले में पीटीआई के गुलाम मोहिउद्दीन दीवान को हराया. पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने बताया कि पीएमएल-एन और पीटीआई ने नेशनल असेंबली में चार चार सीटें जीती हैं जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-कायद ने दो सीटों और एमएमए ने एक सीट जीती है. अब नेशनल असेंबली में विपक्ष की सीटों की संख्या में पांच का इजाफा हुआ है जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन को छह और सीटें मिली हैं. उपचुनावों के नतीजों से संघीय या प्रांतीय सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन इससे विपक्षी दलों को पुनर्जीवित होने में मदद मिलेगी. प्रांतीय असेंबलियों में पीटीआई ने 11 और पीएमएल-एन ने सात सीटें जीती हैं.

पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अगुवाई वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) और अवामी नेशनल पार्टी ने दो दो सीटें तथा निर्दलीय उम्मीदवारों ने दो सीटें जीती हैं. पीएमएल-एन ने पंजाब में 11 सीटों पर चुनाव लड़ा और छह सीटें जीतीं जबकि उसकी प्रतिद्वन्द्वी पीटीआई के खाते में पांच सीटें गईं. पीएमएल-एन ने पीटीआई के गढ़ माने जाने वाले खैबर पख्तूनख्वा में एक प्रांतीय असेंबली सीट भी जीती.परिणामों पर प्रतिक्रिया में सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि अगर उपचुनाव के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान ने चुनाव प्रचार की अगुवाई की होती तो पीटीआई नेशनल असेंबली की 11 में से कम से कम नौ सीटें जीत जाती. एक निजी चैनल से बातचीत में चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा रोक लगाए जाने की वजह से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रचार नहीं किया.

चुनाव आयोग के मुताबिक, 92.8 लाख मतदाता मतदान करने के पात्र थे. आयोग की ओर से डिजाइन किए गए एक खास ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पहली बार विदेशों में बसे पाकिस्तानी नागरिकों ने भी चुनावों में हिस्सा लिया. कुल 7,489 मतदान केंद्रों में सुरक्षा मुहैया कराने के लिए थलसेना के हजारों जवान, पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री रेंजर्स और फ्रंटियर कोर के जवान तैनात किए गए थे. चुनाव आयोग ने 1,727 मतदान केंद्रों को अत्यंत संवेदनशील घोषित किया था जहां अतिरिक्त बल तैनात किए गए थे और सुरक्षा कैमरे भी लगाए गए थे.

अर्जेंटीना में जी20 से इतर होगी मोदी-शी की मुलाकात: चीनी राजदूत

नयी दिल्ली (एजेंसी)।

भारत में चीन के राजदूत लुओ च्यहुई ने सोमवार को कहा कि अर्जेंटीना में अगले महीने होने वाली जी20 की बैठक से इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात होगी। लुओ नयी दिल्ली में अफगान राजनयिकों के लिए आयोजित पहले संयुक्त भारत-चीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम अफगानिस्तान पर चीन-भारत सहयोग की दिशा में पहला कदम है तथा भविष्य में यह और अधिक गहरा होगा। चीनी राजदूत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी नवंबर में जी20 बैठकों से इतर मुलाकात करेंगे। मोदी और शी इस वर्ष दो अनौपचारिक भेंट कर चुके हैं। पहली मुलाकात जून में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन (एससीओ) की बैठक के दौरान वुहान में और दूसरी मुलाकात दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जुलाई में हुई थी। लुओ ने कहा कि चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी दिसंबर में भारत की यात्रा करेंगे।

एक मुल्क ऐसा भी, जिसने बेघर लोगों के सड़क पर रात बिताने पर लगाया प्रतिबंध

बुडापेस्ट (एजेंसी)।

हमारे देश में तो दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में जिनकी सोने के लिए छत नहीं मिलती, वैसे बेघर लोग खुलेआम के नीचे सड़क पर सोकर रात बिता देते हैं लेकिन यूरोप के देश हंगरी में इस मामले में सख्त रुख अपना लिया है. बेघर लोगों के संबंध में प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन सरकार द्वारा लाया गया कानून लागू होने के साथ ही सोमवार से देश में सड़कों पर सोना प्रतिबंधित हो गया है. सरकार के इस कानून को आलोचकों ने ''क्रूर'' बताया है.

हंगरी की संसद ने 20 जून को संविधान में संशोधन कर ''हमेशा सार्वजनिक स्थल पर निवास'' करने को प्रतिबंधित कर दिया. इससे पहले देश ने 2013 में एक कानून बनाकर सार्वजनिक स्थल पर लगातार रहने के लिए जुर्माने का प्रावधान किया था. सरकारी कर्मचारियों ने बताया कि अब पुलिस को सड़कों पर सोने वालों को वहां से हटाने का और उनकी झुग्गियां तोड़ने का पूरा अधिकार होगा. अधिकारी का कहना है कि यह कानून समाज के हितों का ख्याल रखने वाला है.

सामाजिक मामलों की मंत्री अत्तिला फुलोप ने संवाददाताओं से कहा, इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि रात को बेघर लोग सड़कों पर ना बैठे रहें और आम नागरिक बिना किसी दिक्कत के उस जगह का इस्तेमाल कर सकें. सरकारी आश्रयगृहों में करीब 11,000 लोगों के रहने की जगह है लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल कम से कम 20,000 लोग सड़कों पर रहते हैं.

सरकार का कहना है कि वह बेघरों के लिए दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि कर रही है लेकिन अंतरराष्ट्रीय संगठनों और अधिकार समूहों ने नए कानून की आलोचना की है.

एर्दोआन और किंग सलमान ने लापता पत्रकार खशोगी के मुद्दे पर चर्चा की

अंकारा (एजेंसी)।

पत्रकार जमाल खशोगी के लापता होने के बाद पहली बार तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन और अरब के किंग सलमान ने फोन पर बातचीत की और दोनों देशों के बीच विवाद पैदा कर चुके इस मुद्दे पर चर्चा की। बीते दो अक्टूबर को तुर्की के इस्तांबुल स्थित सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में दाखिल होने के बाद से खशोगी लापता हैं। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय के एक सूत्र ने नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर बताया कि एर्दोआन और सलमान ने खशोगी के मुद्दे पर चर्चा की और जांच के दायरे में एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने की अहमियत पर जोर दिया। तुर्की ने पहले कहा था कि सऊदी अरब के एक प्रस्ताव के अनुसार एक कार्य समूह का गठन किया जाएगा। लेकिन अब तक यह पता नहीं चल सका है कि यह काम कैसे करेगा।

सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सलमान ने एर्दोआन के साथ फोन पर हुई बातचीत में तुर्की के साथ अपने देश के ''मजबूत'' रिश्तों की बात कही। किंग सलमान ने एर्दोआन को फोन कर ''संयुक्त कार्य समूह गठित करने के किंगडम के प्रस्ताव का स्वागत करने के लिए शुक्रिया अदा किया ताकि सऊदी नागरिक जमाल खशोगी के लापता होने पर चर्चा हो।''

सलमान ने तुर्की-सऊदी रिश्तों की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि किसी को ''इस रिश्ते की मजबूती को कमजोर'' करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। तुर्की के अधिकारियों का कहना है कि उनका मानना है कि दूतावास के भीतर उनकी हत्या कर दी गई।

तुर्की के मीडिया में भी ऐसे ही दावे प्रकाशित-प्रसारित किए गए हैं। हालांकि, सऊदी अरब ने दूतावास के भीतर खशोगी की हत्या किए जाने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इस बीच, एर्दोआन ने इस मुद्दे पर सतर्कता से कदम उठाया है। उन्होंने अमेरिका के स्थायी निवासी खशोगी के लापता होने के मुद्दे पर चिंता तो जताई है, लेकिन सऊदी अरब पर उनकी हत्या का आरोप नहीं लगाया है।

असांज के लिए आंशिक तौर पर संचार सेवा बहाल करेगी इक्वाडोर सरकार

लंदन (एजेंसी)।

विकिलीक्स ने कहा है कि इक्वाडोर की सरकार लंदन स्थित अपने दूतावास में जूलियन असांज के लिए आंशिक तौर पर संचार सेवा बहाल करेगी। साल 2012 से ही लंदन स्थित इक्वाडोर दूतावास में रह रहे विकिलीक्स के संस्थापक को मार्च में इंटरनेट या मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था ताकि वह बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित नहीं कर सकें। विकिलीक्स ने रविवार को एक बयान में कहा, ''इक्वाडोर ने विकिलीक्स के प्रकाशक जूलियन असांज को बताया है कि शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र के दो वरिष्ठ अधिकारियों और इक्वाडोर के राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो के बीच मुलाकातों के बाद उन्हें अलग-थलग करने के मकसद से उठाए गए कदम वापस ले लिए जाएंगे।''

इस कदम को विकिलीक्स के प्रधान संपादक क्रिस्टीन हैरफैंसन ने ''सकारात्मक'' करार दिया, लेकिन कहा कि यह ''चिंता की बात है कि अपनी राय जाहिर करने की उनकी आजादी अब भी सीमित है।''असांज का संपर्क बाहरी दुनिया से तोड़ देने का फैसला इसलिए किया गया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने दूतावास में रहने के दौरान अन्य देशों के मामलों में दखल नहीं देने का 2017 में किया वादा तोड़ा था। यह जानकारी उस वक्त इक्वाडोर की सरकार ने दी थी। ।

यह कदम तब उठाया गया था जब

असांज ने ट्वीट कर ब्रिटेन के इस आरोप को चुनौती दी कि सैलिसबरी में पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उसकी बेटी पर नर्व एजेंट हमले के लिए रूस जिम्मेदार है। असांज ने पूर्व कैटलन राष्ट्रपति कार्ल्स पुइगडेमोंट की जर्मनी में हुई गिरफ्तारी को लेकर भी हमला बोला था।

अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस छोड़ सकते हैं रक्षा मंत्री का पद: ट्रंप

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को प्रसारित हुए एक साक्षात्कार में रक्षा मंत्री जिम मैटिस को ''डेमोक्रेट की तरह'' बताते हुए कहा कि वह अपना पद छोड़ सकते हैं। सीबीएस के रविवार को प्रसारित ''60 मिनट्स'' कार्यक्रम में ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह चाहते हैं कि मैटिस पद छोड़ दें। इस पर ट्रंप ने कहा, ''ऐसा हो सकता है कि वह छोड़ दें। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वह एक तरह से डेमोक्रेट हैं। लेकिन जनरल मैटिस अच्छे व्यक्ति हैं। हम साथ में बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। वह पद छोड़ सकते हैं। मेरा मतलब है कि एक वक्त हर कोई जाता है।'' ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दो दिन पहले मैटिस के साथ लंच किया था और नौसेना के सेवानिवृत्त चार स्टार वाले जनरल मैटिस ने उन्हें बताया था कि वह पद छोड़ रहे हैं। ट्रंप ने अपने मंत्रिमंडल में बदलाव के संकेत दिए थे जिसके बाद उन्होंने मैटिस पर यह टिप्पणी की। गत सप्ताह ही संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निक्की हेली ने अचानक इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। राष्ट्रपति ने कहा, ''मैं चीजें बदल रहा हूं और मैं इसका अधिकार रखता हूं। मेरे पास अब लोग हैं जो असाधारण साबित होंगे। वे प्रशासन में आएंगे, वे असाधारण साबित होंगे।'' उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि हमारे पास बड़ा अच्छा मंत्रिमंडल है। कुछ लोग हैं जिनसे मैं खुश नहीं हूं और मेरे पास कुछ अन्य लोग भी हैं जिनमें मैं बेहद खुश हूं।''

बीजिंग: धुंध के लिए प्रदूषण नहीं जिम्मेदार, परफ्यूम-हेयर जेल से बढ़ रहा प्रदूषण

बीजिंग (एजेंसी)।

चीन के विशेषज्ञों ने देश में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए हेयर स्प्रे, परफ्यूम और एयर रिफ्रेशर में पाए जाने वाले वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों को जिम्मेदार बताया है. सोमवार को बीजिंग में छाई जबरदस्त धुंध के बीच विशेषज्ञों का यह बयान आया है. बीजिंग में वायु गुणवत्ता सूचकांक 213 तक पहुंच गया, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने ÷अत्यंत अस्वास्थ्यकर÷ की श्रेणी में वर्गीकृत किया है. बीजिंग में दो करोड़ दस लाख से अधिक लोग रहते हैं. यहां हर साल वायु प्रदूषण की समस्या रहती है.

हाल के वर्षों में सरकार द्वारा शुरू किए गए उपायों के बाद से प्रदूषण में कुछ हद तक गिरावट आई है. 2015 से किये गए इन उपायों में कोयले का सीमित इस्तेमाल और प्रदूषण उद्योगों को क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करना शामिल है. चीन वर्षों से धुंध के खिलाफ कठिन संघर्ष रहा है. इसने कुछ चीनी क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा में कटौती की है. सरकार ने अपने नागरिकों से जबरदस्त प्रदूषण के दिनों में खुद को बचाने के लिए मास्क और वायु शोधक (एयर प्यूरीफायर) खरीदने को कहा है.

चार-स्तरीय चेतावनी प्रणाली

बीजिंग में प्रदूषण के लिए चार-स्तरीय चेतावनी प्रणाली है, जिसमें उच्चतम चेतावनी लाल है इसके बाद नारंगी, फिर पीली और अंत में नीली चेतावनी होती है. नारंगी चेतावनी का मतलब है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के लगातार तीन दिनों के लिए 200 से अधिक होने का अनुमान है. हाई अलर्ट के दौरान, भारी प्रदूषक वाहनों और निर्माण कचरे वाले ट्रकों का चलना प्रतिबंधित कर दिया जाता है. कुछ निर्माण फर्मों की ओर से उत्पादन में कटौती की जाती है.

बीजिंग नगर पर्यावरण संरक्षण ब्यूरो ने बताया कि जनवरी से सितंबर तक, बीजिंग में पीएम 2.5 की औसत सांद्रता में पिछले वर्ष की तुलना में 16.7 प्रतिशत की गिरावट हुई है. बीजिंग और चीन के उत्तरी हिस्से में भारी प्रदूषण और ऑटोमोबाइल के उत्सर्जन की वजह से प्रदूषण के कारणों पर कई अध्ययन किए गए हैं. विशेषज्ञों ने अब शहर में खराब वायु गुणवत्ता के लिए अस्थिर अथवा वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (वीओसी) को जिम्मेदार बताया है.

वीओसी कार्बन आधारित रसायनों का एक समूह है, जो कमरे के तापमान पर आसानी से वाष्पित हो जाता है. पेंट और सफाई उत्पादों जैसे कई आम घरेलू सामग्रियों और उत्पादों से भी वीओसी निकलता है. सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा है कि वीओसी यौगिकों में पीएम 2.5 का स्तर 12 प्रतिशत है.

आखिरकार ट्रंप ने स्वीकार किया कि अफवाह नहीं है जलवायु परिवर्तन

वॉशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जलवायु परिवर्तन को अफवाह बताने वाले अपने पुराने दावे से रविवार को पलट गए लेकिन उन्होंने कहा कि यह मानवजनित और स्थाई प्रभाव नहीं है और जलवायु में ''फिर परिवर्तन होगा।''सीबीएस न्यूज के '60 मिनट' के साथ साक्षात्कार में ट्रंप ने वैज्ञानिकों के पास ''बड़ा राजनीतिक एजेंडा'' होने का आरोप लगाया और दुहराया कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिहाज से काम करते हुए वह अमेरिका को नुकसान की स्थिति में नहीं देखना चाहते हैं।

अमेरिका ग्रीन हाउस गैसों का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। यह पूछने पर कि क्या वह अभी भी जलवायु परिवर्तन को अफवाह मानते हैं, ट्रंप ने कहा, ''मुझे लगता है कि कुछ हो रहा है। कुछ बदल रहा है और उसमें दोबारा बदलाव होगा। मुझे नहीं लगता कि यह अफवाह है, मुझे लगता है कि संभवत: कुछ फर्क है। लेकिन मुझे नहीं पता है कि यह मानवजनित है।''अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ''मैं यही कहूंगा। मैं हजारों-हजार अरब डॉलर नहीं देना चाहता।

मैं लाखों-करोड़ों नौकरियां नहीं गंवा सकता। मैं नुकसान की स्थिति में नहीं आना चाहता।'' जलवायु परिवर्तन को कभी अफवाह बताने वाले ट्रंप ने जून, 2017 में अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकाल लिया था। उनका दावा था कि 190 से ज्यादा देशों के बीच हुए पेरिस समझौते में भारत और चीन जैसे देशों को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाया गया है जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था और नौकरियों को इससे खतरा है।

मुख्यमंत्री आवास के बहाने लाखों की ठगी करनेवाला सलाखों के पीछे

सूरत। मुख्यमंत्री आवास योजना में लैट दिलाने के बहाने लोगों से 87.20 लाख वसूलकर धोखाधड़ी करनेवाले को पुलिस ने धरदबोचा।

चौक बाजार पुलिस सूत्रों के अनुसार कोजवे रोड श्रद्धादीप सोसायटी निवासी संदीप परषोत्तम अणधण सहित लोगों से उगत नहर, रांदेर निवासी रोहित मोती सोलंकी ने मुख्यमंत्री आवास योजना के एल.आई.जी. वन में 80 छोटे लैट और 16 बड़े लैट ड्रॉ पद्धति से दिलाने का विश्वास दिया और दो साल बीतने के बावजूद लैट नहीं दिलाकर संदीप अणधण समेत लोगों से धोखाधड़ी कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने संदीप की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। इस बीच सूचना के आधार पर आरोपी को कोजवे के पास से गिरफ्तार कर लिया।

मगदल्ला में बंगले से 1.15 लाख की चोरी

सूरत। शहर के डुमस रोड मगदल्ला हरिओम बंग्लोज निवासी के बंग्ले को चोरों ने निशाना बनाकर तिजोरी से 90 हजार और गहने मिलाकर 1.15 लाख का सामान चोरी कर फरार हो गए। उमरा पुलिस सूत्रों के अनुसार मगदला हरिओम बंग्लोज निवासी दिव्यांग राजू पटेल के बंगले को गत रोज दोपहर डेढ बजे से शाम साढे 6 बजे के दौरान किसी अज्ञात ने अपने घर के बाहर के पहली मंजिल की बाल्कनी खिड़की से बेडरूम में प्रवेश किया और बेडरूम के तिजोरी से नगद 90 हजार और गहने सेमत 1,15,000 रूपए के सामान चोरी कर फरार हो गए।

गुजरात में सड़क हादसों में प्रति दिन 20 लोग गंवाते हैं जान

सूरत। केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक हिट एन्ड रन दुर्घटना में गुजरात दूसरे क्रम पर है। वर्ष 2017 में दुर्घटना के कुल 19081 मामले दर्ज हुए। जबकि 7289 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई7 गुजरात में दिन ब दिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लोगों में ड्राइविंग सेन्स के अभाव में किसी गलती के कारण निर्दोष लोगों को जान गंवानी पड़ती है7 केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में खराब सड़कों के कारण हुई दुर्घटना में 228 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में वर्ष 2017 के दौरान दुर्घटना के 1908 1 मामले दर्ज हुए। जिसमें 7289 लोगों की मौत हो गई7 इस प्रकार राज्य में प्रति दिन 20 लोगों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है। इस साल गुजरात दुर्घटना से 985 पदयात्रियों की छोटी-मोटी चोटें आईं। देश में सबसे अधिक दुपहिया वाहन गुजरात में है, जिससे फोर व्हील से अधिक दुपहिया वाहनों की दुर्घटना में मृतांक अधिक है। तेज र तार के कारण 5948 लोगों की दुर्घटना में मौत हो गई। जबकि रोंग साइड में वाहन चलाने की घटना में 377 लोग मौत के शिकार हो गए। इसके अलावा वाहन चलाते समय मोबाइल के उपयोग करते 37, लाइटिंग के कारण 21 और नशे की हालत में वाहन चलाने वाले 18 लोग मौत के मुंह चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में प्रति एक लाख की आबादी पर 30 दुर्घटनाएं होती हैं। जबकि गोवा में 193 दुर्घटना, केरल में 107 और तमिलनाडु में 94 दुर्घटना दर्ज हुई। इन तीन राज्यों के मुकाबले गुजरात थोड़ा सुरक्षित कहा जा सकता है। दुर्घटना में होनेवाले मौत के मामलों की पिछले तीन साल से तुलना की जाए मृतांक में औसत घटा है। जो सडक हादसे में मौत का आंकड़ा 8000 था जो अब 7289 हो गया है। गुजरात के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2145 दुर्घटनाएं दर्ज हुई हैं। जबकि राज्य के हाईवे पर 2376 और दूसरे छोटे-बड़े रास्तों पर 2768 दुर्घटनाएं हुई।

गुजरात में जीका वायरस को लेकर विशेष अलर्ट जारी

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने पड़ोसी राज्य राजस्थान में फैले जीका वायरस के संक्रमण के मद्देनजर विशेष अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने राजस्थान से आने वाले लोगों और जीका वायरस संक्रमण के लक्षणों वाले लोगों पर विशेष रूप से नजर रखने के लिए चेतावनी जारी की है। जीका वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान के लिए एयरपोर्ट, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर मेडिकल टीमों की तैनाती की जाएगी। अस्पतालों को भी ऐसे मामलों की तुरंत सूचना देने को कहा गया है। भारत में जीका वायरस संक्रमण का पहला मामला जनवरी 2017 में गुजरात के अहमदाबाद में पाया गया था। राजस्थान के जयपुर में गत 22 सितंबर को 85 साल की एक महिला में इसका संक्रमण पाए जाने के बाद अब तक 55 से अधिक ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। एडीस मच्छर से फैलने वाली इस बीमारी से गर्भवती महिलाओं के गर्भस्थ शिशुओं को विशेष नुकसान होता है।

अल्पेश ठाकोर के सिर पर एक करोड़ रुपए का ईनाम

अहमदाबाद। उत्तरी गुजरात के राधनपुर सीट से कांग्रेस विधायक और ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर के सिर कलम करनेवाले को एक करोड़ रुपए ईनाम देने की महारानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड घोषणा की है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को हमले करने और गुजरात से उन्हें भगाने के मामले से चर्चा में आए अल्पेश ठाकोर के खिलाफ उत्तर भारतीय लोगों में जबर्दस्त आक्रोश है। महारानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड का खुद को अध्यक्ष बताने वाले भवानी ठाकुर ने कहा कि गुजरात में ठाकोर और उसके साथी राक्षसी प्रकृति के हैं जो दबे-कुचले गरीब मजदूरों से मारपीट कर कायरता दिखा रहे हैं और देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। जिसके खिलाफ सभी को एकजुट होना चाहिए। अल्पेश ठाकोर के सिर एक करोड़ का ईनाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश के बहराईच में इसके पोस्टर चस्पा किए गए हैं।

पीढ़ी में उजागर हो इसके लिए सरकार ने उदासीनता

गुजरात भारत की एकता का प्रतीक : आदित्यनाथ

गुजरात ने देश के नायक सरदार पटेल को विश्व की सबसे ऊंची स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा द्वारा श्रद्धाजंलि

गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि, देश की एकता अखंडिता को तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों को सभी देशवासी एक होकर विफल बनाये इसके लिए सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची स्टेच्यू ऑफ यूनिटी राइट टाइम फॉर राइट जॉब है। उन्होंने कहा है कि, सरदार साहब ने देश को जोड़ने का काम किया है इसे कोई तोड़ नहीं सकता है । यदि सरदार साहब नहीं होते तो आज भारत का नक्शा अलग होता । मुख्यमंत्री ने लखनऊ में आयोजित हुए एकता संवाद में स्पष्ट कहा है कि, राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता, इतिहास और धरोहर आज की पीढ़ी में उजागर हो इसके लिए पहले की केन्द्र सरकार ने उदासीनता अपनाकर पूरी पीढ़ी को देश के लिए समर्पण करनेवाले कई महानुभाव के इतिहास से वंचित रखने की जो साजिश की गई थी । इस संदर्भ में विजय रुपाणी ने बताया है कि, एक ही परिवार को महत्व देकर गांधीजी के साथ अन्याय हुआ । सरदार साहब को भी भुला देने के इरादापूर्वक प्रयास हुए। पार्लामेन्ट में उनकी तस्वीर भी रखने में देरी की गई । वीर सावरकर के कारावास के स्थल आंदामान की सेल्युलर जेल को स्मारक के तौर पर अटलजी ने मंजूरी दी है । विजय रुपाणी ने बताया कि, आंबेडकरजी के जीवन के साथ जुड़ी हुई पांच महत्वपूर्ण स्थल लंदन के अपने पढ़ाई स्थल जन्म स्थल में दिल्ली में महापरी निर्वाण स्थल पर स्मारक नागपुर दीक्षा भूमि और मुंबई की चैत्य भूमि में स्मारक निर्माण भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करने का संकल्प लिया है यह भी बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि, एक और अखंड भारत के शिल्पकार सरदार साहब के यह महान कार्य और इतिहास को विश्व के सामने उजागर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने २०१३ में यह विश्व की ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास करके हरएक राज्य के लोगों का भावनात्मक लगाव सरदार साहब के साथ जोड़ा है । यह प्रतिमा निर्माण में देश के किसानों के खेत औजारों का लोहा इस्तेमाल किया गया है।

बोर्ड की परीक्षा को लेकर सरकार का निर्णय

कक्षा-१० और १२ की परीक्षा फीस में से मुक्ति

कक्षा-१० और १२ में करीब सात लाख से ज्यादा विद्यार्थिनी और आठ हजार से ज्यादा दिव्यांगों को लाभ

गांधीनगर। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली मार्च २०१९ की कक्षा-१० और कक्षा-१२ की बोर्ड की परीक्षा की रजिस्ट्रेशन-परीक्षा फीस में से पहली बार दिव्यांगों और विद्यार्थिनियों को मुक्ति दी गई है। मार्च-२०१९ में ली जाने वाली कक्षा-१०, कक्षा-१२ सामान्य प्रवाह और १२ विज्ञान प्रवाह की परीक्षा में करीब सात लाख विद्यार्थिनियों का रजिस्ट्रेशन होगा। जबकि दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या करीब ८ हजार से ज्यादा होगा। राज्य सरकार ने इस वर्ष में बोर्ड परीक्षा फीस माफी के लिए २८.४२ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विद्यार्थी के लिए परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में स्कूल स्तर पर ऑनलाइन शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद कई विद्यार्थिनी और कितने दिव्यांग विद्यार्थी परीक्षा दे रहे है इसकी निश्चित आंकड़े मिले सरकार फीस माफी की रकम की शिक्षा विभाग को भरपायी की जाएगी।

सरकार ने एक समय में विद्यार्थिनियों और दिव्यांगों को परीक्षा फीस में से मुक्ति देने की घोषणा करने के बाद जुलाई महीने में ली गई पूरक परीक्षा में इसे लागू किया गया था। जुलाई में कक्षा-१० की पूरक परीक्षा में ३२,०८७, विद्यार्थिनियों और ९२८ दिव्यांगों की फीस माफ की गई थी। ज बकि कक्षा-११ सामान्य प्रवाह में ३२,७५३ विद्यार्थिनियों और ६६५ दिव्यांगों, कक्षा-१२ विज्ञान प्रवाह में ३५१३ और १८ को परीक्षा फीस में मुक्ति दी गई थी। राज्यभर में हर वर्ष कक्षा-१० में १० लाख से ज्यादा और सामान्य प्रवाह तथा विज्ञान प्रवाह में कक्षा-१२ में ६ लाख से ज्यादा इस तरह करीब १७ लाख विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा के लिए रजिस्टर होता है, जिसमें ३५ प्रतिशत संख्या विद्यार्थिनी होती है। परीक्षा फीस नहीं लगने के कारण शिक्षा विभाग को आय की होनेवाली कमी सरकार भरपायी करेगी। फिलहाल में ही शिक्षा विभाग ने प्रतिक्षेत्र बोर्ड की परीक्षा के लिए रजिस्टर होते विद्यार्थियों के लिए इन्टरनेट और प्रिन्ट की सुविधा के तहत १० रुपये भरपायी करने की घोषणा की है।

ग्रामीण एलसीबी कस्टडी में युवक की संदिग्ध मौत

अहमदाबाद। सुरेन्द्रनगर में रहते और ट्रान्सपोर्ट कंपनी में ड्राइवर के तौर पर नौकरी करता एक युवक की ग्रामीण एलसीबी पुलिस की कस्टडी में मौत होने की घटना सामने आने पर पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। दूसरी तरफ मृतक युवक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है कि पुलिस ने चोरी की आशंका में हिरासत में लेकर पिटाई करने पर इसकी मौत हो गई। परिजनों द्वारा यह पूरे मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। भारी विवाद और हंगामें के बाद अब उच्च पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की रिपोर्ट मांगने की दिशा में भी काम शुरू किया गया है। युवक की मौत के मामले में पुलिस ने सोमवार को सुबह में ही इसके परिजनों को जानकारी दे दी। युवक की कब मौत हुई इस मामले में पुलिस ने परिवार को स्पष्टता नहीं की है। हाल परिजनों का पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराने के लिए बोपल पुलिस स्टेशन पहुंचे होने की जानकारी मिली है।

आरटीओ ऑफिस देर रात तक काम

नये वाहनों के रजिस्ट्रेशन के बैकलॉग की वृद्धि हुई

अहमदाबाद। आरटीओ की वाहन संबंधित सभी कामकाज अब अहमदाबाद में ही नहीं राज्यभर में ऑनलाइन अनिवार्य किया गया है। मेन्युअल कामकाज की तुलना में ऑनलाइन कामकाज की प्रक्रिया में तेजी आयी है, फिर भी राज्य की सबसे बड़ी अहमदाबाद सुभाषब्रिज आरटीओ में नये वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए पांच हजार से ज्यादा वाहनों का बैकलॉग होने पर आरटीओ ऑफिस को उजागर करके भी यह कामकाज लाइन अप करना अनिवार्य हो गया है। नवरात्रि त्यौहार की शुरूआत के साथ ही अब त्यौहारों की सीजन अब शुरू हो रही है। नवरात्रि के दिनों में आठम और दशहरा को सबसे ज्यादा नये वाहनों की बिक्री होती है। इस समय में नये रजिस्टर्ड हुए वाहनों के काम का बैकलॉग ज्यादा संख्या में बढ़ सकती है। इसी वजह से आरटीओ प्रशासन ने अभी पुराना बैकलॉग दूर करने के लिए आधी रात तक ऑफिस खुला रखकर कामकाज करने का शुरू किया गया है। १ अगस्त से सभी आरटीओ में ऑनलाइन सिस्टम शुरू की गई है, जिसमें नये वाहनों के रजिस्ट्रेशन और पार्सिंग की विधि ऑनलाइन की जा रही है। नये वाहन जिस मालिक ने खरीदा हो इसके सभी पेपर्स डीलरों को ऑनलाइन अपलोड करना होता है और एक ही सॉफ्टवेयर के द्वारा यह ऑनलाइन अपलोड हुए पेपर्स आरटीओ में बैठे इंस्पेक्टर जांच कर सकते है। पेपर सहित सभी डॉक्युमेन्ट चेक करने के बाद आरटीओ इसे ऑनलाइन एप्रूवल देता है और रजिस्ट्रेशन का पेमेन्ट होने के बाद आरसी बुक के लिए इसे गांधीनगर रीफर किया जाता है। गुजरात में वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। गत वर्ष १० लाख से भी ज्यादा नये वाहनों का रजि स्ट्रेशन हुआ था। राज्य की आरटीओ में हर एक मिनट पर ३ वाहन रजिस्टर होते हैं। गत वर्ष नये १७.३१ लाख वाहन रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। वाहन का ऑनलाइन पेमेन्ट (टैक्स और फीस सहित) डॉक्युमेन्ट अपलोड, मालिक का तबादला, एड्रेस में बदलाव, डुप्लीकेट आरसी बुक वाहन रजिस्ट्रेशन आदि सभी सेवा के लिए ऑनलाइन अनिवार्य किया गया है।

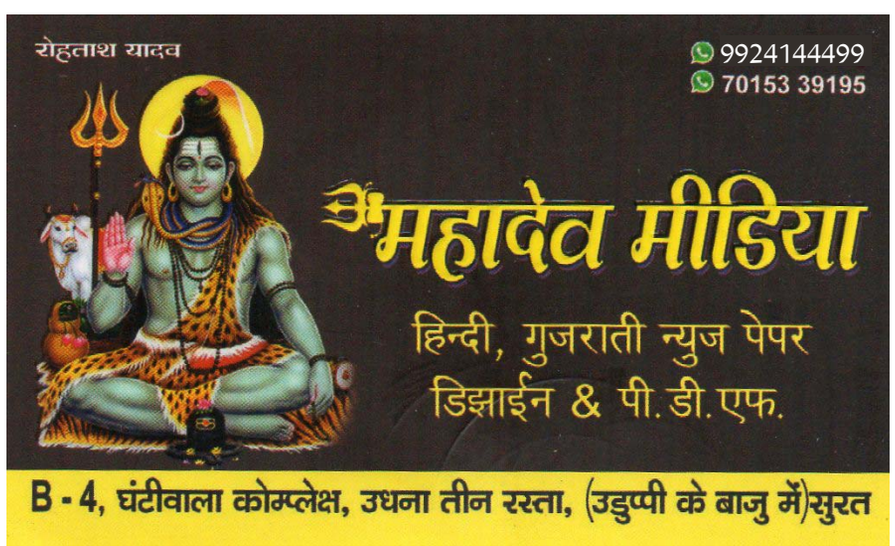

शेर और बाध की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा गंभीर भेदभाव

अहमदाबाद। गीर में २३ शेरों की मौत मामले में सोमवार को गुज रात हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई प्रारंभ हुई थी, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए कोर्ट सहायक द्वारा कई महत्व की सूचना दी गई। जिसमें विशेष करके पूरे विश्व में एक अलग पहचान और गुजरात के गौरव समान एशियाटीक शेर की देखभाल और सुरक्षा के पीछे राज्य सरकार द्वारा वर्ष में सिर्फ ९५ हजार रुपये का खर्च किया जाता है, जबकि इसके सामने बाघ के पीछे १५ लाख रुपये खर्च किए जाते होने का भेदभाव तो होने का भेदभाव अपनाये जाते होने का कोर्ट को इस बारे में बताया गया है।

श्री जीण संघ द्वारा 14वीं ध्वज चुनर धर्म यात्रा का अद्भुत का आयोजन

सूरत। सूरत की अग्रणी सामाजिक एवं धार्मिक संस्था श्री अखिल भारतीय जीण माता सेवा संघ सूरत द्वारा हर वर्ष नवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित होने वाली ध्वज चुनर धर्म यात्रा रविवार को 14वी ध्वज चुनर धर्म का आयोजन किया गया। ज्ञातव्य हो कि जात-पात से परे माँ नाम से अभिभूत सूरत का हर लाडला इस यात्रा में जुड़ा। इस धर्म यात्रा में सूरत के लगभग 238 सामाजिक और धार्मिक संगठन सहयोगियो ने हिस्सा लिया।

इस वर्ष के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 151 फ़ीट लम्बा ध्वज रहा। विशाल ध्वजा 21 दिव्यांग बच्चों द्वारा माँ बाण-अम्बा को अर्पित किया गया।

सामाजिक समरसता के क्षेत्र में श्री जीण संघ द्वारा बाल्मिकी समाज से 11 माँ स्वरूपा कन्याओं का चरण प्रक्षापण कर कुंकुम चावल से पूजा की गई सामाजिक समरसता की ओर एक और कदम बढ़ाते हुये श्री जीण संघ द्वारा बाल्मिकी समाज से 4 जोडों (महिला-पुरुष) को आमंत्रित किया गया है जो कि माँ जीण अम्बा की ज्योत लेकर ,माँ को चुनरी ओढ़ाया। साथ ही इस विशाल ध्वज चुनर धर्म यात्रा की प्रथम हनुमान ध्वजा बाल्मिकी समाज के इन जोडों को अर्पित की गई। ऐसा करके समाज के उपेक्षति वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया।

माँ लक्ष्मी स्वरूपा बाण जीण को अतिप्रिय 121 गन्ने का महाभोग सुअर्पित किया गया। विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ,जब माँ के भक्त हाथों में सैकड़ो गन्ने लिये बाण माता के द्वार पर जाकर उन्हें यह महाभोग सुअर्पित किया गया।।

सूरत पुलिस द्वारा जनहित में जारी 100 डायल करने के 100 कारण नाम से एक मुहिम शुरू की गई थी। इस मुहिम के अंतर्गत अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी को मध्यनज़र रखते हुये, लोगों में जागरूकता बढ़ाने हेतु श्री जीण संघ द्वारा *विशेष पैम्पलेट्स एवं विशाल 4×6 के पोस्टर बनवाये गये जिसमें 100 नंबर डायल करने के 100 कारण की सम्पूर्ण जानकारी का समविष्टिकरण किया गया।

अतिथि विशेष के रूप म पदमश्री कनुभाई पटेल व आरआरएस विभाग सूरत महानगर संघचालक सुरेश भाई मास्टर भी जीण संघ के इस समारोह में उपस्थित हुए।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com